





## केजरीवाल का दावा

# भाजपा कटवा रही आप समर्थकों के वोट



मतदाता सूची को लेकर भाजपा पर निशाना साधते आप प्रमुख अर्थविद केजरीवाल, साथ में मनीष सिंहसिंहदाय।

● बोले, शाहदरा विस में 11,018 वोट कटवाने के लिए आवेदन दिया है, इनमें 75 फीसद जीवित हैं।

● 18 अक्टूबर के बाद से विस चुनाव तक एक भी वोट काटने की अनुमति न दी जाए।

पार्यनियर समाचार सेवा। नई दिल्ली

फरवरी में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर राष्ट्रीय राजधानी में राजनीतिक सरार्हा बढ़ गई है। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अर्थविद केजरीवाल ने भाजपा के विलाक हमलावर खर अपना रखा है। शुक्रवार को केजरीवाल ने एक बार इसीआईएसीवीप को भी टैग किया है।

-जिला मणिस्ट्रेट (शाहदरा)

हैं, भाजपा 11 हजार (6 फीसद) वोट कटवाना चाहती है, जबकि पिछली बार आप यहां से मात्र 5,294 वोट से जीती थीं, फिर चुनाव का क्या मतलब। केजरीवाल ने कहा कि इसमें चुनाव आयोग की भूमिका बहुत सांदिध्य है। चुनाव आयोग का काम नहीं किया गया है। रोजाना जितने लोगों के बोट करने का आवंदन आते हैं। चुनाव आयोग को उसकी जानकारी अपनी वेबसाइट पर फार्म नंबर 10 में डालनी होती है और बताना होता है कि वह उसपर कार्रवाई कर रहा है। लेकिन उनके नाम मतदाता सूची से हटाए दिए गए हैं। उन्होंने चुनाव आयोग की भूमिका को भी संदिध्य बताया और आरोप लगाया कि भाजपा की तरफ से वोट काटने के आ रहे आवेदन वेबसाइट पर नहीं डाला जा रहा है।

अर्थविद केजरीवाल ने संवाददाता सम्मेलन में कहा कि चुनाव आयोग से हम इस वोट डिल्लीशन घोटाले की जांच की मांग करते हैं। उन्होंने कहा कि 18 अक्टूबर के बाद से विधानसभा चुनाव तक एक भी वोट काटने की अनुमति न दी जाए। केजरीवाल के वोट कटवाने की जांच की जीत रही है, यह संज्ञें नहीं पूरी तरह प्रयोग की पालताना में तय नीतिगत सांजिश है।

भाजपा के पदाधिकारी द्वारा दायर इस विलापन आवेदन को ईडीआरओ द्वारा विधिवत स्वीकार किया गया था।

इसके अलावा, जो अधिक चौंकाने वाला है वह यह है कि इस तरह के दुर्भाग्यान्वय अनुरोध प्राप्त करने के बाद, ईआरओ ने अपने ईडीआरओ और बीएलओ को 22 नवंबर 2024 को एक पत्र जारी करके विलापन की प्रक्रिया शुरू की।

इस पत्र में ईडीआरओ और बीएलओ को सत्यानन्द और उसके बाद विलापन की प्रक्रिया शुरू करने के लिए कहा गया था।

आम आदमी पार्टी ने कहा कि वह पूरी जिम्मेदारी से कहते हैं कि अक्टूबर-नवंबर 2024 में भाजपा के बीएलए 1 ने शाहदरा एसी-62 के 500 की जांच की तो 372 लोग ऐसे मिले जो जीवित हैं और उसी पते पर रह रहे हैं। आप संयोजक ने कहा कि शाहदरा में 1,86,362 वोटर

## भाजपा कटवा रही वोट : देवन्द्र

नई दिल्ली। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष देवन्द्र यादव ने कहा कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में संविधान के अंगत मतदान करने का अधिकार सबको बराबर दिया गया है, जबकि मौजूदा नारायणों को वोट करने की सांजिश जो भाजपा कर रही है वह सांवित करता है कि भाजपा भविष्य में अस्तित्व को लेकर असुरक्षित है। पूरा देश समझ रहा है कि विदेश और विपरित परिस्थितियों के बावजूद भाजपा कैसे देश और प्रदेश में चुनाव में संविधान के अंगत नीतिगत सांजिश है।

सहनभूत लेने के लिए केजरीवाल वोटर के नाम कटवाए जा रहे हैं, क्या उनके नाम और उनके वोटरों को खोज रहा हुआ है, जो संवाददाता सम्मेलन करके बताना दे रहे हैं कि उनके वोटरों के नाम काटे जा रहे हैं। यह सही है कि भाजपा सांजिश से वोट कटवा रही है।

भाजपा के पदाधिकारी द्वारा दायर इस विलापन आवेदन को ईडीआरओ द्वारा विधिवत स्वीकार किया गया था।

इसके अलावा, जो अधिक चौंकाने वाला है वह यह है कि इस तरह के दुर्भाग्यान्वय अनुरोध प्राप्त करने के बाद, ईआरओ ने अपने ईडीआरओ और बीएलओ को 22 नवंबर 2024 को एक पत्र जारी करके विलापन की प्रक्रिया शुरू की।

इस पत्र में ईडीआरओ और बीएलओ को सत्यानन्द और उसके बाद विलापन की प्रक्रिया शुरू करने के लिए कहा गया था।

भाजपा के पदाधिकारी द्वारा दायर इस विलापन आवेदन को ईडीआरओ द्वारा विधिवत स्वीकार किया गया था।

इसके अलावा, जो अधिक चौंकाने वाला है वह यह है कि इस तरह के दुर्भाग्यान्वय अनुरोध प्राप्त करने के बाद, ईआरओ ने अपने ईडीआरओ और बीएलओ को 22 नवंबर 2024 को एक पत्र जारी करके विलापन की प्रक्रिया शुरू की।

इसके अलावा, जो अधिक चौंकाने वाला है वह यह है कि इस तरह के दुर्भाग्यान्वय अनुरोध प्राप्त करने के बाद, ईआरओ ने अपने ईडीआरओ और बीएलओ को 22 नवंबर 2024 को एक पत्र जारी करके विलापन की प्रक्रिया शुरू की।

इसके अलावा, जो अधिक चौंकाने वाला है वह यह है कि इस तरह के दुर्भाग्यान्वय अनुरोध प्राप्त करने के बाद, ईआरओ ने अपने ईडीआरओ और बीएलओ को 22 नवंबर 2024 को एक पत्र जारी करके विलापन की प्रक्रिया शुरू की।

इसके अलावा, जो अधिक चौंकाने वाला है वह यह है कि इस तरह के दुर्भाग्यान्वय अनुरोध प्राप्त करने के बाद, ईआरओ ने अपने ईडीआरओ और बीएलओ को 22 नवंबर 2024 को एक पत्र जारी करके विलापन की प्रक्रिया शुरू की।

इसके अलावा, जो अधिक चौंकाने वाला है वह यह है कि इस तरह के दुर्भाग्यान्वय अनुरोध प्राप्त करने के बाद, ईआरओ ने अपने ईडीआरओ और बीएलओ को 22 नवंबर 2024 को एक पत्र जारी करके विलापन की प्रक्रिया शुरू की।

इसके अलावा, जो अधिक चौंकाने वाला है वह यह है कि इस तरह के दुर्भाग्यान्वय अनुरोध प्राप्त करने के बाद, ईआरओ ने अपने ईडीआरओ और बीएलओ को 22 नवंबर 2024 को एक पत्र जारी करके विलापन की प्रक्रिया शुरू की।

इसके अलावा, जो अधिक चौंकाने वाला है वह यह है कि इस तरह के दुर्भाग्यान्वय अनुरोध प्राप्त करने के बाद, ईआरओ ने अपने ईडीआरओ और बीएलओ को 22 नवंबर 2024 को एक पत्र जारी करके विलापन की प्रक्रिया शुरू की।

इसके अलावा, जो अधिक चौंकाने वाला है वह यह है कि इस तरह के दुर्भाग्यान्वय अनुरोध प्राप्त करने के बाद, ईआरओ ने अपने ईडीआरओ और बीएलओ को 22 नवंबर 2024 को एक पत्र जारी करके विलापन की प्रक्रिया शुरू की।

इसके अलावा, जो अधिक चौंकाने वाला है वह यह है कि इस तरह के दुर्भाग्यान्वय अनुरोध प्राप्त करने के बाद, ईआरओ ने अपने ईडीआरओ और बीएलओ को 22 नवंबर 2024 को एक पत्र जारी करके विलापन की प्रक्रिया शुरू की।

इसके अलावा, जो अधिक चौंकाने वाला है वह यह है कि इस तरह के दुर्भाग्यान्वय अनुरोध प्राप्त करने के बाद, ईआरओ ने अपने ईडीआरओ और बीएलओ को 22 नवंबर 2024 को एक पत्र जारी करके विलापन की प्रक्रिया शुरू की।

इसके अलावा, जो अधिक चौंकाने वाला है वह यह है कि इस तरह के दुर्भाग्यान्वय अनुरोध प्राप्त करने के बाद, ईआरओ ने अपने ईडीआरओ और बीएलओ को 22 नवंबर 2024 को एक पत्र जारी करके विलापन की प्रक्रिया शुरू की।

इसके अलावा, जो अधिक चौंकाने वाला है वह यह है कि इस तरह के दुर्भाग्यान्वय अनुरोध प्राप्त करने के बाद, ईआरओ ने अपने ईडीआरओ और बीएलओ को 22 नवंबर 2024 को एक पत्र जारी करके विलापन की प्रक्रिया शुरू की।

इसके अलावा, जो अधिक चौंकाने वाला है वह यह है कि इस तरह के दुर्भाग्यान्वय अनुरोध प्राप्त करने के बाद, ईआरओ ने अपने ईडीआरओ और बीएलओ को 22 नवंबर 2024 को एक पत्र जारी करके विलापन की प्रक्रिया शुरू की।

इसके अलावा, जो अधिक चौंकाने वाला है वह यह है कि इस तरह के दुर्भाग्यान्वय अनुरोध प्राप्त करने के बाद, ईआरओ ने अपने ईडीआरओ और बीएलओ को 22 नवंबर 2024 को एक पत्र जारी करके विलापन की प्रक्रिया शुरू की।

इसके अलावा, जो अधिक चौंकाने वाला है वह यह है कि इस तरह के दुर्भाग्यान्वय अनुरोध प्राप्त करने के बाद, ईआरओ ने अपने ईडीआरओ और बीएलओ को 22 नवंबर 2024 को एक पत्र जारी करके विलापन की प्रक्रिया शुरू की।

इसके अलावा, जो अधिक चौंकाने वाला है वह यह है कि इस तरह के दुर्भाग्यान्वय अनुरोध प्राप्त करने के बाद, ईआरओ ने अपने ईडीआरओ और बीएलओ को 22 नवंबर 2024 को एक पत्र जारी करके विलापन की प्रक्रिया शुरू की।

इसके अलावा, जो अधिक चौंकाने वाला है वह यह है कि इस तरह के दुर्भाग्यान्वय अनुरोध प्राप्त करने के बाद, ईआरओ ने अपने ईडीआरओ और बीएलओ को 22 नवंबर 2024 को एक पत्र जारी करके विलापन की प्रक्रिया शुरू की।

इसके अलावा, जो अधिक चौंकाने वाला है वह यह है कि इस तरह के दुर्भाग्यान्वय अनुरोध प्राप्त करने के बाद, ईआरओ ने अपने ईडीआरओ





# दक्षिण कोरिया में संकट

## मार्शल ला की घोषणा

दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति यून सुक युवोल ने थोड़े समय के लिए मार्शल ला की घोषणा कर दी। इसका देश में भारी विरोध तथा दुनिया में निन्दा हुई। स्थिर लोकतंत्र और समृद्धि के लिए दुनिया भर के आकर्षण का केन्द्र रहे दक्षिण कोरिया में मार्शल ला की घोषणा की गई। दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति यून सुक युवोल ने अपनी स्थिति तथा गिरती लोकप्रियता बचाने के लिए यह अतिवादी कदम उठाया। लेकिन अब उनको अपने राष्ट्रपति कार्यकाल की सबसे कठोर चुनौती का सामना करना पड़ रहा है। मार्शल ला लगाने के विवादास्पद नियन्य की व्यापक विपरीत प्रतिक्रिया हुई जिससे देश गंभीर राजनीतिक संकट में घिर गया। इसके परिणामस्वरूप भारी विरोध प्रदर्शन हुए, उनके इस्तीफे की मांग की गई और अब उनके खिलाफ महाभियोग की तैयारी हो रही है। यून ने राष्ट्रीय सुरक्षा सरोकारों तथा ‘राज्य-विरोधी तत्वों’ के सपाए के लिए मार्शल ला की घोषणा की थी। लेकिन बहुत से लोग इस कदम को बढ़ते राजनीतिक और व्यक्तिगत घोटालों को देखते हुए सत्ता पर पकड़ मजबूत करने का प्रयास मानते हैं। इसकी प्रतिक्रिया त्वरित व बहुत गंभीर हुई, विधि निर्माताओं ने आदेश वापस लेने के लिए व्यापक विरोध प्रदर्शन किए और भारी संख्या में लोग सियोल की सड़कों पर जमा हो गए। हालांकि, कुछ ही घंटे के भीतर यून ने आदेश वापस ले लिया, पर इससे जनता का गुस्सा शांत नहीं हुआ और उनको नुकसान उठाना पड़ा।



विपक्ष-निर्यात्रित नेशनल असेम्बली के कारण पैदा तनाव शामिल हैं। अप्रैल के संसदीय चुनावों में डेमोक्रेटिक पार्टी की भारी विजय से भी यून राजनीतिक रूप से और अलग-थलग हो गए। उत्साही विपक्ष ने यून के प्रशासन से जुड़े महत्वपूर्ण प्रशासनिक अधिकारियों के खिलाफ महाभियोग के कदम तेज किए जिससे राष्ट्रपति का कामकाज करना कठिन हो गया। मार्शल ला की घोषणा ऐसे राष्ट्रपति का अंतिम प्रयास था जिनका समर्थन लगातार घट रहा है तथा अपनी पार्टी के भीतर भी विरोध बढ़ रहा है। वास्तव में यह कदम बड़ी गलती थी जो दयनीय रूप से विफल हो गया और अब उसके नकारात्मक राजनीतिक परिणाम सामने हैं। इस घटना से विपक्ष द्वारा यून के खिलाफ महाभियोग प्रयास तेज हुए हैं और सत्तारूढ़ पार्टी के कुछ सदस्य खुलेआम उनके इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। अभूतपूर्व रूप से बहुत बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारी सड़कों पर उतरे तथा श्रम संगठनों ने यून के इस्तीफे देने तक राष्ट्रव्यापी हड्डताल की धमकी दी है। इस संकट ने दक्षिण कोरिया के मित्रों में भी खतरे की घंटियां बजा दी हैं जिनमें अमेरिका और जापान ने गंभीर चिन्ता प्रकट की है। उनको सबसे बड़ी चिन्ता इस बात की है कि उत्तर कोरिया इस आंतरिक अर्शांति का लाभ उठा कर दक्षिण कोरिया के खिलाफ तनाव बढ़ा सकता है जिससे पूरे क्षेत्र में अस्थिरता और बढ़ेगी। इस प्रकार दक्षिण कोरिया वर्तमान समय में अपनी लोकतांत्रिक दृढ़ता की कठोर परीक्षा दे रहा है। मार्शल ला के फैरन वापस लेने की घोषणा से स्पष्ट है कि दक्षिण कोरिया में संस्थागत नियंत्रणों और संतुलनों की स्थिति बहुत मजबूत बनी हुई है। लेकिन आगे के रास्ते पर सरकारीपूर्वक चलना होगा ताकि एशिया के एक सबसे जीवन्त लोकतांत्रिक देश में और धर्मीकरण न होने पाए तथा उसका स्थायित्व सुनिश्चित रहे।

डोनाल्ड ट्रम्प  
टैरिफ और  
निर्यात नियंत्रण  
के साथ बिडेन  
के सख्त रुख  
को और मजबूत  
करने के लिए  
तैयार हैं।

9

## एमएसएमई का महत्व

**भारतीय अर्थव्यवस्था** में एमएसएमई के महत्व को कम करके नहीं आंका जा सकता। वे नवाचार को बढ़ावा देते हैं, रोजगार पैदा करते हैं और निर्यात तथा जीड़ीपी में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। उद्यमशीलता को बढ़ावा देने और बढ़े पैमाने पर औद्योगिकीकरण का समर्थन करके, एमएसएमई क्षेत्रीय असंतुलन को कम करने, आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्गों के उथान और सामाजिक-आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उनकी अनुकूलनशीलता और लचीलापन उन्हें आर्थिक प्रतिकूलताओं का सामना करने में अपरिहार्य बनाता है, जिससे भारतीय अर्थव्यवस्था की विनियोगीता बढ़ती है।

**डोनाल्ड ट्रम्प**  
**टैरिफ़ और**  
**निर्यात नियंत्रण**  
**के साथ बिडेन**  
**के सख्त रुख**  
**को और मजबूत**  
**करने के लिए।**

**द** निया की दो सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं, अमेरिका और चीन के लिए भरी हुई बूंदों सामने आ गई हैं, इससे पहले कि मूल हार्ड हिटर डोनाल्ड ट्रम्प अगले साल जनवरी में नए राष्ट्रपति के रूप में कार्यभार संभालते। अपने अंतिम चीन को निर्वित करने उपयोग में से एक में निवर्तमान राष्ट्रपति जो बिडेन ने चीन को उच्च-स्तरीय चिप्स, चिप बनाने वाले उपकरणों पर अतिरिक्त निर्यात नियंत्रण लगाया है, जिनका उपयोग घटकों के रूप में या हथियारों के निर्माण में भी किया जा सकता है। नए प्रतिबंध सीधे चीन के कुछ सबसे बड़े चिप निर्माताओं को भी लक्षित करते हैं, इस प्रकार ड्रैगन के आक्रामक हथियारीकरण कार्यक्रम में गश्तान्पत्र अधिक में अधिक लाभार्थी

झालते हैं। चीन ने गैलियम, एंटीमनी आदि जैसे महत्वपूर्ण खनियों के निर्यात पर जवाबी नियंत्रण लगाया, जो चिप्स के आवश्यक घटक हैं। जब इन उपयोगों की घोषणा की जा सकी

थी, तब भी राष्ट्रपति चुनाव डोनाल्ड ट्रम्प ने 9 सदस्य ब्रिक्स देशों को 100 प्रतिशत टैरिफ की धमकी दी थी, आगर वे डॉलर के लिए एक वैकल्पिक वैश्विक मुद्रा बनाने का विकल्प चुनते हैं। श्री ट्रम्प ने पहले ही कनाडा, मैक्सिको और यूरोपीय संघ को टैरिफ स्केलपेल से धमकाया है, जब तक कि वे उनके पास ऐसे प्रस्तावों के साथ वापस नहीं आते जिन्हें अनदेखा करना मुश्किल है। ट्रम्प का तीसरा प्रसंदीदा शब्द टैरिफ है, जिसका उपयोग वे सहयोगियों और दुष्प्रभावों के साथ व्यापार सौदों पर बातचीत करने के लिए करते हैं। जिन देशों ने डोनाल्ड ट्रम्प से उच्च टैरिफ के नवीनतम खतरे का सामना किया है, उन्होंने पहले से ही सख्त व्यवसायी के साथ बातचीत करने के लिए एक सतर्क दृष्टिकोण अपनाया है। कनाडा और मैक्सिको ने कहा है कि टैरिफ मुद्रों पर उनका सामना करने की तकलीफ में रुपांतर अपेक्षिता के



साथ सौदे को और बेहतर बनाने में अधिक रुचि होगी। चीन जानता है कि ट्रम्प अपने पूर्ववर्ती जो बिडेन की तुलना में उन मुद्दों पर अधिक स्पष्ट होंगे, जहां अमेरिका उन्हें प्रत्यक्ष खतरा मानता है। चीनी सरकार के मुख्यपत्र ग्लोबल टाइम्स में हाल ही में प्रकाशित संपादकीय में से एक में, इंटरनेट सोसाइटी ऑफ चाइना, चाइना एसोसिएशन ऑफ अंतर्राष्ट्रीय टेक्नोलॉजीज ने चाइना सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री एसोसिएशन और चाइना एसोसिएशन ऑफ कम्प्युनेक्शंस एंटरप्राइजेज को अमेरिकी चिप्स का असुरक्षित और अविश्वसनीय बताते हुए बयान जारी करने के लिए उद्धृत किया गया है। इसमें आगे कहा गया है, अमेरिका ने इस उपाय का इस्तेमाल अपनी शक्ति का बहुत अधिक विस्तार करने के लिए किया है और जिसमें जापान, जीटीएलैंड, इंडिया इत्यादि

## आप की बात

## नोटों की गङ्गी, जांच का विषय

न शादी न ब्रात, न रिसेप्शन न बाजार, न कोई खरीदारी और न ही कोई दान-पूण्य के लिए भगवान् का मंदिर। ये तो लोकतंत्र का मंदिर है जहाँ निस्वार्थ जनसेवा के लिए जनहित और देशहित में निर्णय लेने हेतु चुने हुए प्रमुख जनप्रतिनिधियों की सभा आयोजित की जाती है। यहां नोटों का क्या काम वो भी 100-200 या 500-1000 नहीं पूरी 500 (कुल 50000) के नोटों की गड़ी वो भी जनप्रतिनिधि की गद्दी पर। सभापति के पूछने पर जबाब मिलता है ये गड़ी मेरी नहीं है। मैं तो संसद में केवल 500 का नोट लाता हूँ। वाई 500 का नोट ही क्यों लाते हो खुल्ले (चिल्लर) भी तो लासकते हों। क्योंकि 500 के नोट से ज्यादा जरूरत पड़ती है छोटे नोटों की घर से बाहर निकलने पर। वैसे दिल्ली जैसे बड़े शहर में तो 500-1000 तो सामान्य आदमी को भी अपनी जेब में लेकर चलना पड़ते हैं तब वे तो जाने-माने वकील और जनप्रतिनिधि हैं। केवल 500 रुपये ? बात कुछ जमी नहीं। ठीक है हो सकता है गाड़ी सरकारी, खाना-पीना संसद की डायरी में मैटेंड तब नगद 500 रुपये काफी हैं। यूं तो आजकल डिजिटल करेंसी का जमाना है। गूगल पे, पेटीएम, एटीएम व मोबाइल याने सारी दुनिया मुझी में समझा। वैसे भी ये कुछ लोगों को विपक्ष की साजिश लग रही है किन्तु पहले भी संसद में लाखों रुपये उड़ाने की घटना घट चकी है।

- शकुंतला महेश नेनावा, इंदौर

गंभीर आरोप

महोदय , संवित पात्रा द्वारा लोकसभा में राहुलगांधी व वीपक्षी दलों पर लगाया गये विदेशियों के हाथों कठपुतली बन कर नाचने के आरोप गंभीर हैं। हमारे देश में मीडिया को अत्यधिक स्वतंत्रता के कारण विदेशी पैसा प्राप्त करके सरकार के हर काम में रोड़े अटकने की निरंतर प्रयास होते रहे हैं। कई बार हमने देखा है कि राहुलगांधी के विचार और पाकिस्तान तथा भारत विरोधी संस्थाओं के विचार एक समान होते हैं। बल्कि राहुल गांधी विदेश से फैलाए गए भ्रम जाल को भारत में और मजबूती प्रदान करते हैं। इतना ही नहीं खुद विदेशों में जाकर भी भारत विरोधी विचारधारा वाले सक्रिय लोगों से भेंट करते हैं। भारत सरकार की कट्ट आलोचना करते हैं। और बिना सबूत के कुछ भी अर्नगल बयान बाजी करते रहते हैं। सरकार को अब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर होनेवाली व्यर्थ बहसों पर सख्त पाबंदी लगाना चाहिए। प्रेस की स्वतंत्रता के नाम पर देशके लोगों के बीच सोची समझी साजिश के तहत भ्रम फैलाना और लोगोंको सरकार के खिलाफ भड़काने की कोशिशों को सख्ती से रोकना होगा। बार-बार चुनाव में जनता जब इन्हें नकरी चुकी है। तो यह भ्रम फैलाने के नए-नए हथकड़े अपनाते हैं। हाल ही में तो एक एक चुनाव क्षेत्र बेलेटों पेपर पर फिर से मतदान करवाने के योजना बध्द प्रयास किए थे ताकि ईंवीएम को और चुनाव आयोग को गलत ठहरा सके।

सुखबीर बादल पर हमला

ਪੱਜਾਬ ਕੇ ਪੂਰ੍ਬ ਫਿਟੀ ਸੀਏਮ ਸੁਖਵੀਰ ਬਾਦਲ ਪਰ ਸ਼ਵਣ ਮੰਦਿਰ ਮੈਂ ਜਾਨਲੇਵਾ ਹਮਲਾ ਕਿੱਥੀਆਂ ਕਾ ਸੰਸਥ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹਾ ਹੈ। ਬਢੇਂ ਹੁਣ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੇ ਭਿੰਡਰਾਵਾਲਾ ਕੀ ਸਮੂਤੀ ਕੋ ਤਾਜਾ ਕਰ ਦਿਯਾ ਹੈ। ਜਬ ਸ਼ਵਣ ਮੰਦਿਰ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀਆਂ ਕਾ ਗੁਢੇ ਬਨ ਗਈ ਥਾ। ਖੋਪ ਕੇ ਕਾਰਣ ਖੁਦ ਸਿਖ ਸਮੁਦਾਯ ਕੇ ਲੋਗ ਭੀ ਤਹਿੰਦੇ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਸਕੇ। ਆਜ ਵੈਸੀ ਹੀ ਪਰਿਸਥਿਤੀਆਂ ਬਨ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਸਮਰੱਥਨ ਖੁਲੇਅਮ ਇੰਦਿਆ ਗਾਂਧੀ ਕੀ ਹਤਾ ਕਾ ਮਹਿਸਾ ਮੰਡਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਚੈਲੋੜ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਹਮਨੇ ਇੰਦਿਆ ਜੀ ਕੋ ਨਹੀਂ ਛੋਡਾ ਤਾਂ ਕਿਸੀ ਅਨ੍ਯ ਕੀ ਮਾਰਨਾ ਮਾਮੂਲੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਪੱਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰ

ਸਰਕਾਰ ਕੋ ਮਿਲਕਰ ਸਥਿਤੀ ਕੋ ਸਥਾਨੀ ਕੇ ਸਾਥ ਸੀਓ ਕਾਬੂ ਮੈਂ ਕਰਨਾ ਹੋਗਾ। ਅਨ੍ਯਥਾ ਯਹ ਰੋਗ ਨਾਸੂਰ ਬਨ ਜਾਏਗਾ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਲ ਹੋਨੇ ਕੇ ਕਾਰਣ ਤਹਿੰਦੇ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਸੇਨਾ ਦੇ ਸੁਰੱਖਾ ਭੀ ਮਿਲਤੀ ਰੋਗੀ ਕਾਰੋਬਿਕ ਸੇਨਾ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਲਾਂ ਪਰ ਸੀਧੇ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸਾਥ-ਹੀ-ਸਾਥ ਹਮ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਲਾਂ ਪਰ ਰਾਣ੍ਝ ਰਾਣ੍ਝ ਵਿਰੋਧੀ ਗਤਿਵਿਧੀਆਂ ਹੋਣੇ ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਸੇਨਾ ਕੋ ਸੀਧੇ ਹਵਾਤਕ੍ਸੇਪ ਕਰਨੇ ਕੀ ਛੂਟ ਹੋਨਾ ਚਾਹੀਏ। ਤਾਕਿ ਰਾਣ੍ਝ ਵਿਰੋਧੀ ਸ਼ਕਤਿਆਂ ਵਿਖੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਲਾਂ ਕਾ ਸ਼ਰਣਗਾਹ ਕੇ ਰੂਪ ਮੌਜੂਦ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ।

पाठक अपनी प्रतिक्रिया ई-मेल से  
responsemail.hindipioneer@gmail.com

par�ीभेजसकते हैं।











